भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1027

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

नवोदय विद्यालय (एनवी) और केन्द्रीय विद्यालय (केवी)

†1027. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

श्री राजकुमार रोत:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सम्पूर्ण देश में नवोदय विद्यालयों (एनवी) और केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में छात्रों के प्रवेश की भारी मांग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले के मुख्यालयों में कम से कम एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के बापटला जिले में नवोदय विद्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में नए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का है और यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ड.) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान देश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र में भौतिक सुविधाएं और शिक्षण संकाय प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयंत चौधरी)

(क) केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में केंद्रीय विद्यालयों (केवि) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जनवि) में प्रवेश की भारी मांग है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा-1 में प्रवेश के लिए 888059 छात्रों ने पंजीकरण कराया और उपलब्ध सीटों के लिए 75703 छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश मिला। जहां तक जवाहर

नवोदय विद्यालयों का संबंध है, जनवि चयन परीक्षा के आधार पर मुख्य रूप से कक्षा-VI में प्रवेश दिया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जनवि में कक्षा-VI में प्रवेश के लिए 49640 सीटों के लिए 2500887 छात्रों ने पंजीकरण कराया।

(ख) से (घ) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) खोलने की परिकल्पना की गई है। नवंबर 2016 में 62 नए जनवि को स्वीकृति देने के साथ, 100% शहरी आबादी वाले 6 जिलों को छोड़कर, इस योजना को स्वीकार करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 638 जिले (31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार), इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राजस्थान राज्य के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में एक-एक जनवि वर्ष 1987-88 से कार्य कर रहा है और बांसवाड़ा जिले (एसटी से केंद्रित) में एक अतिरिक्त जनवि भी स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के नवगठित बापटला जिले में जनवि नहीं है। तथापि, नए विभाजित जिले जिसमें जनवि स्वीकृत नहीं है, के छात्र को एकीकृत अविभाजित पुराने जिले में स्थित जनवि में प्रवेश के लिए उपस्थित होने की अनुमति है।

नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह स्थायी भवन के निर्माण के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए और स्थायी भवन का निर्माण होने तक स्कूल चलाने के लिए आवश्यक किराए से मुक्त, अस्थायी भवन, उपलब्ध कराए। नए जनवि को स्वीकृत करना और उन्हें खोलना मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है।

(ङ) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों सहित पूरे देश में दो पूर्णतः वित्तपोषित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात् केन्द्रीय विद्यालय योजना और नवोदय विद्यालय योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। भारत सरकार देशभर में क्रमशः नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलने और उन्हें चलाने के लिए सहायता अनुदान के रूप में नवोदय विद्यालय समिति (नविस) और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) को बजटीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में देश भर में 1253 केवि और 653 जनवि कार्यरत हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान न.वि.स. और के.वि.सं. को आवंटित सहायता अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	नविस को आवंटित बजट	केविसं को आवंटित बजट
2019-20	3068.00	6331.40
2020-21	3480.00	6437.68
2021-22	3800.00	6800.00
2022-23	4920.30	7461.25
2023-24	5486.50	8500.00

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा को भी क्रियान्वित कर रहा है और इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, वंचित समूहों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों (बीपीएल) की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक कस्तूरबा गांधी बालिका (केजीबीवी) आवासीय विद्यालय का प्रावधान है। केजीबीवी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं। समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित केंद्र के हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	**आवंटित बजट**
2019-20	35905.26
2020-21	27957.32
2021-22	30000.00
2022-23	32514.69
2023-24	33000.00

*****